

①

राज कुमार शौर्ष

आसिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
विभाग

जी. जे. कालेज, रामबाग, बिहटा, पटना

B.A. II Paper - III

राज्य सभा

- * राज्य सभा संसद का प्रथम या उच्च सदन है।
- * यह एक स्थायी सदन है। यह न तो कभी भंग होती है और न ही नये सिरे से इसका निर्माण होता है।

संरचना

राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है जिसमें 238 निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान समय में राज्यसभा की वास्तविक संख्या 245 है।

सीटों के आवंटन का आधार

भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रथम 50 लाख की जनसंख्या के आधार पर 5 सीटें प्राप्त होंगी तथा 20 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सीटें प्राप्त होंगी।

धुला मतदान

(2)

जन प्रातिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा चुनाव में धुला मतदान आयोजित होगा।

निवास

वर्ष 2003 से ~~अधिनियम~~ संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारतीय भू-भाग में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति राज्यसभा निर्वाचन में किसी भी राज्य से भाग ले सकता है।

निर्वाचन के लिए नामांकन

जनप्रातिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार राज्यसभा निर्वाचन के लिए 10 हजार की जमा राशि भरनी पड़ती है तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल के उम्मीदवारों का समर्थन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का 10 प्रतिशत अथवा 10 विधानसभा सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए जो भी इसमें कम हो

कार्यकाल

राज्यसभा एक स्थाई निकाय है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्यो में यथासम्भव

3) एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्त हो जाता है।

योग्यता

राज्य सभा के सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है।

1-> वह भारत का नागरिक हो।

2-> राज्य सभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु का होना आवश्यक है।

3-> सर्वोच्च आयोग के द्वारा अधिकृत एवं तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करना आवश्यक है।

4-> इसके अतिरिक्त संविधान में संसद को योग्यता निर्धारित करने की शक्ति दी गई है।

अयोग्यता

1-> उसने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण न किया हो।

2-> दिवाखिया न हो।

3-> किसी सभ्य न्यायालय के द्वारा उसे विरुद्ध चिन्त

का घोषित न किया गया हो

(4)

प → भारत की नागरिकता का ह परित्याग कर दिया हो अथवा
स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया हो

(1) → अयोग्यता का निर्धारण

संविधान में राज्यसभा एवं लोक सभा सदस्यों की
योग्यता का एकसमान प्रावधान है एवं अयोग्यता के तरीके
एकसमान हैं। संविधान में उल्लिखित अयोग्यता का निर्धारण
निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।

I → जनजातिनिधित्व अधिनियम, 1951

II → दल-बदल कानून के अनुसार

III → दोहरी सदस्यता

सभापति :-

उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति
होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का पालन कर
रहा होता है तब उपसभापति सभापति के दायित्वों का निर्वहन
करता है।

कार्य एवं शक्तियाँ

कार्य एवं शक्तियों के ठीक दृष्टिकोण से राज्य सभा कम प्रभावशाली है किन्तु इसको बिल्कुल ही महत्वहीन नहीं आका जा सकता है क्योंकि गैर-धन विधेयक को दोहराने की सहमति प्राप्त होना आवश्यक है। यदि दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है।

राज्य सभा की कुछ विशेष शक्तियाँ

1 → राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।

2 → राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आरक्षित भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है।

3 → उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य सभा आरम्भ कर सकती है।

राज्य सभा का महत्व

6

1 → राज्यों का प्रतिनिधित्व

2 → वरिष्ठों का सदन

3 → पुनरीक्षणकारी सदन